भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 955
उत्तर देने की तारीख 08 फरवरी, 2022
19 माघ, 1943 (शक)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देना

955. कुमारी अगाथा के. संगमा :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर 2021 के ओलंपिक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों की हाल की सफलता को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2018 से वितरित की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया के कार्यान्वयन का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त खिलाड़ियों को खेलो इंडिया योजना द्वारा गारंटीशुदा 5 लाख रु. प्रति वर्ष के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय सहायता भी देने पर विचार कर रही है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, यह मंत्रालय खेलों को व्यापक आधार प्रदान करने और खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के उद्देश्य से कई स्कीमें लागू करता है । खेलो इंडिया स्कीम के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों की 439.51 करोड़ रु. की 64 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है । इसके अलावा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंफाल, मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है । इसके अलावा, गुवाहाटी, असम में 2009-10 से लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) का एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र भी कार्य कर रहा है ।

(ख) इस मंत्रालय की खेलो इंडिया स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 08 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और 152 खेलो इंडिया केंद्र संस्वीकृत किए गए हैं । इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 22 खेल अकादमियों को भी मान्यता दी गई है और 02 सेना बाल खेल कंपनियों को सहायता दी जा रही है । पूर्वोत्तर क्षेत्र से कुल 195 खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की गई है । निधियां स्कीम-वार जारी की जाती हैं, राज्य-वार नहीं । खेलो इंडिया स्कीम के आरंभ से लेकर अब तक आबंटित निधियों और किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु.)

वर्ष	**आबंटित राशि**	**वास्तविक व्यय (30.01.2022 तक)**
2016-17	118.10	118.10
2017-18	350.00	346.99
2018-19	375.09	342.24
2019-20	578.00	575.52
2020-21	338.93	338.93
2021-22	657.71	395.00

(ग) खेलो इंडिया स्कीम के "राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य खेल अकादमियों को सहायता" घटक के तहत मान्यता प्राप्त अकादमियों को खेलो इंडिया एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए प्रति एथलीट प्रति वर्ष 6,28,400/- रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें 1,20,000/- रु. का ऑउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) भी शामिल है । टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत, सरकार भारत के शीर्ष खिलाड़ियों को ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए उनकी तैयारी में सहायता प्रदान करती है । कोर समूह के एथलीटों को प्रति माह 50,000/- रु. का ओपीए दिया जाता है । ओपीए के अलावा खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण प्लान का पूरा खर्च टीओपीएस के तहत वहन किया जाता है । इसके अलावा, टीओपीएस विकास समूह के एथलीटों को 25,000/- रु. का ओपीए और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में विशेष प्रशिक्षण सहायता दी जाती है ।

****